कॉरपोरेट सर्किल मुख्यालय लखनऊ दूसरे, गौतमबुद्धनगर तीसरे, बरेली जोन पांचवें नंबर पर आया

प्रदेश में जीएसटी संग्रह में मेरठ टॉप पर

रिकॉर्ड

■ सलीम अहमद

मेरठ। जीएसटी कलेक्शन में अप्रैल माह में मेरठ जोन के राज्य कर विभाग के अफसरों ने रिकार्ड बना दिया। देशभर में अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन अव्वल रहा साथ ही मेरठ जोन में अप्रैल में 211.87 करोड़ का राजस्व संग्रह हुआ। मेरठ सूबे में टॉप पर है, जबकि कॉरपोरेट सर्किल मुख्यालय लखनऊ दूसरे, गौतमबुद्धनगर तीसरे, लखनऊ द्वितीय जोन चौथे नंबर पर और बरेली जोन पांचवें नंबर पर आया है।

राज्य कर विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक मेरठ का अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन 147.34 करोड़ रुपये था। अप्रैल 2025 में 287.08 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया। इसमें मेरठ राज्य कर विभाग के अफसरों ने 211.87 करोड़ का राजस्व संग्रह कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। राज्य कर विभाग मेरठ जोन के अपर आयुक्त ग्रेड-1 हरिराम चौरसिया एवं अपर आयुक्त ग्रेड-2 आरपी मल्ल ने बताया अप्रैल 2025 में राजस्व संग्रह में पूरे प्रदेश में मेरठ ने पहला स्थान हासिल किया है।

राजस्व संग्रह में टॉप फाइव राज्य कर विभाग के जोन की स्थिति

जोन	राजस्व लक्ष्य	अप्रैल 2025 में संग्रह	अप्रैल 2024 में संग्रह
मेरठ	287.08 करोड	211.87 करोड़	147.34 करोड़
लखनऊ	1428.15 करोड़	1023.40 करोड़	969.10 करोड़
गौतमबुद्धनगर	1874.25 करोड़	1275.75 करोड़	1003.98 करोड़
लखनऊ द्वितीय	1628.30 करोड़	1096.32 करोड़	915.75 करोड़
बरेली	305.15 करोड़	203.05 करोड़	161.33 करोड़

खंड और संभागवार राजस्व संग्रह की स्थिति

मेरठ खंड-1 का राजस्व संग्रह	लक्ष्य का 266 फीसदी
शत प्रतिशत राजस्व संग्रह वाले खंड	खंड-4, 5, 6 और 7
संभाग-ए राजस्व संग्रह	109 फीसदी
संभाग-बी राजस्व संग्रह	52.63 फीसदी
कारपोरेशन राजस्व संग्रह	72.37 फीसदी

> मेरठ जोन में अप्रैल वर्ष 2024-25 में 147.32 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह हुआ, लेकिन अप्रैल 2025-26 में मेरठ जोन में 211.87 करोड़ का राजस्व संग्रह कर रिकॉर्ड कायम कर सूबे में पहला स्थान हासिल किया।
> **- आरपी मल्ल, अपर आयुक्त ग्रेड-2 राज्य कर विभाग**

> जीएसटी राजस्व संग्रह में देशभर में रिकॉर्ड बना। मेरठ जोन (मेरठ-बागपत) ने प्रदेश में राजस्व संग्रह में पहला स्थान हासिल किया है। इसका श्रेय करदाता व्यापारियों और कर संग्रह अफसरों-कर्मचारियों को जाता है।
> **- हरिराम चौरसिया, अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर विभाग**

मार्च महीने में शराब दुकानों के लिए आवेदन से ही विभाग को करीब 32 करोड़ रुपये राजस्व मिला था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल माह में पिछले साल के मुकाबले जिले में शराब बिक्री से विभाग को 130 फीसदी अधिक राजस्व मिला है। जो एक रिकॉर्ड है। **-प्रदीप कुमार सिंह, जिला आबकारी अधिकारी**

अप्रैल में शराब बिक्री से 103 करोड़ का राजस्व

आबकारी विभाग ने मार्च माह में राजस्व संग्रह कर सरकारी खजाने में योगदान किया ही था। अप्रैल में भी शराब की हुई बिक्री से 103 करोड़ का राजस्व जिले में आबकारी विभाग को प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष अप्रैल माह में शराब बिक्री से आबकारी विभाग को 78.96 करोड़ का राजस्व मिला था। पिछले साल अप्रैल के मुकाबले इस बार अप्रैल में 42.04 करोड़ अधिक राजस्व आया।